टाइटल कोड - MPHIN7675
Email- haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

प्रधान संपादक - विवेक जैन

वर्ष 01 अंक 05 | जुलाई 2022 | पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रुपये

शीर्ष सरकारी वैज्ञानिक ने किया चौंकाने वाला खुलासा

क्या गेहूं की गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं कुछ किसान!

हलधर किसान। रबी सीजन 221-22 में गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज कि गई है। इस गिरावट के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट में एक शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा है कि भारत में गेहूं के जीन बदलने की दिशा में कोशिशें की जा रही हैं। गेहूं की किस्मों को मौसम के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा सका है। हालांकिए इस वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर कहाए गर्मी में अच्छी पैदावार वाली किस्में विकसित की गई हैं, लेकिन जिन इलाकों में ऐसी वेराइटी का प्रयोग हो रहा हे, वहां गेहूं की पैदावार या गुणवत्ता से समझौता भी होता है। बता दें कि भारत में इस साल 2 साल में सबसे कम गेहूं का उत्पादन हुआ है।

दरअसल, भीषण गर्मी के कारण इस साल भारत में 20 साल में सबसे कम गेहूं का उत्पादन हुआ है। पंजाबए उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेशों के किसान फसल खराब होने के कारण लाखों रुपये के घाटे और कर्ज के बोझ से दबे होने की बात कर रहे हैं। खुद कृषि मंत्रालय ने उत्पादन पूर्वानुमान घटा दिया है। ऐसे में गेहूं की खेती करने वाले किसानों के बीच कई आशंकाएं हैं।

खेती में अधिक पानी की खपत गेहूं की खराब फसल या कम उत्पादन का प्रमुख कारण हीटवेव रहा है। खेती पर मौसम के प्रभाव के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी अध्ययनों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में उच्च वाष्पीकरणीय की मांग देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वाष्पीकरण डिमांड बढ़ने के कारण खेती में पानी की खपत 30: अधिक हो रही है।

पर्यावरण बचाने के प्रयास काफी नहीं

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में शीर्ष सरकारी वैज्ञानिक ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चेतावनियां गंभीर हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के उपाय उतनी तेज गति से नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी सहन करने वाली गेहूं की किस्मों की खोज और विकास के प्रयास हो रहे हैं।

गेहूं की गुणवत्ता से समझौता ! एचटी की रिपोर्ट में सरकारी वैज्ञानिक के हवाले से कहा गया, भारत में मौजूद गेहूं की तमाम किस्मों में जर्मप्लाज्म की स्क्रीनिंग पर काम चल रहा है, लेकिन हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जहां गेहूं का जीन आसानी से बदला जा सके। वैज्ञानिक ने बताया कि जहां गर्मी प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं, इन इलाकों में गेहूं की पैदावार या गुणवत्ता से समझौता होता है।

भीषण गर्मी में 'झुलसा गेह' मौसम की मार के कारण 20 साल में सबसे कम उत्पादन

गेहूं की गुणवत्ता से समझौता ! एचटी की रिपोर्ट में सरकारी वैज्ञानिक के हवाले से कहा गया, भारत में मौजूद गेहूं की तमाम किस्मों में जर्मप्लाज्म की स्क्रीनिंग पर काम चल रहा है, लेकिन हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जहां गेहूं का जीन आसानी से बदला जा सके। वैज्ञानिक ने बताया कि जहां गर्मी प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं, इन इलाकों में गेहूं की पैदावार या गुणवत्ता से समझौता होता है।

मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मानसा जिले के गेहूं किसान गुरबख्श नागी के खेत में पकने वाले गेहूं के डंठल सुनहरे पीले रंग के बाद भूरे रंग में बदल गए। ये फसल खराब होने यानी भीषण गर्मी में फसलों और दानों के सिकुड़ने का संकेत था।

कृषि मंत्रालय ने घटाया उत्पादन पूर्वानुमान उत्तर प्रदेश भी पंजाब की तरह बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यूपी में गेहूं की पैदावार में 18 प्रतिशत की गिरावट आई। हरियाणा में गेहूं 19 प्रतिशत कम पैदा हुआ। तीन प्रमुख राज्यों में गेहूं उत्पादन में गिरावट के कारण कृषि मंत्रालय ने शुरुआती उत्पादन पूर्वानुमान 111.32 मिलियन टन से 5प्रतिशत घटाकर 106.41 मिलियन कर दिया है। वास्तविक संख्या इससे और भी कम हो सकती है। आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में, बठिंडा और मानसा में गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक 30 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई है।

गेहूं की कम पैदावार का दूरगामी असर गेहूं की पैदावार के संबंध में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो वैज्ञानिकों ने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जारी किए हैं। इस पद्धति से वैज्ञानिकों को पैदावार निर्धारित करने में मदद मिलती है। इसी पद्धति से फसल के नुकसान का भी आकलन होता है। 20 साल में गेहूं की कम पैदावार के संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके दीर्घकालिक असर देखे जा सकते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए मशहूर इलाके भौगोलिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में जलवायु पूर्वानुमानों से पता चलता है कि जल्द ही अगर कोई उपाय नहीं किए गए तो गर्मी और बढ़ेगी।

रूस से भारत में होगा 3.5 लाख टन खाद का आयात

हलधर किसान। खरीफ सीजन में खाद की किल्लत के बीच भारत ने लगभग 3.5 लाख टन डाई. अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का रुस से आयात किया है। जुलाई महीने तक डीएपी की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। रुस.यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों द्वारा रुस पर व्यापार प्रतिबंध लगाए जाने के बीच यह आयात किया गया है।

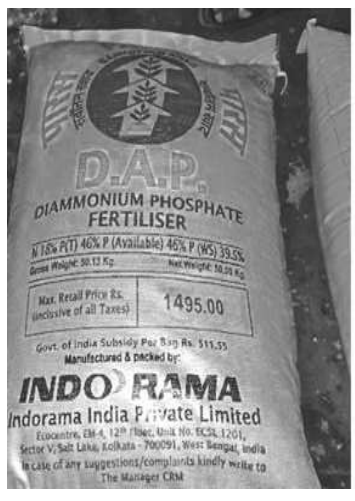

डीएपी के आयात के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स और कृषक भारती कोऑपरेटिव द्वारा 920.925 डॉलर प्रति टन, कॉस्ट प्लस फ्रेट (सीएफआर) की कीमत पर अनुबंध किया गया था। भारत द्वारा डीएपी की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि अन्य देशों की तुलना में कम है। इस आयात से किसानों को राहत मिलेगी। कृषि के नजरिए से देखें तो खाद का यह आयात बिलकुल सही समय पर हुआ है। खरीफकी फसल की बुआई शुरू हो चुकी है। खाद की सही समय पर और सही मात्रा मे आपूर्ति होने का अर्थ है किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर खाद मिलने की संभावना।

जानकारी अनुसार रूस के पहले चीन भारत के लिए डीएपी खाद का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था। इसके अलावा हमारी खाद मुख्य रूप से मोरक्को और सऊदी अरब से आती थी। अंतराष्ट्रीय हालात को देखते हुए रूस इस वक्त नाजुक स्थिति में है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के चलते रूस के पारंपरिक खरीदार कम हो गए हैं। ऐसे में भारत के लिए यह कीमतें निगोशिएट करने का कूटनीतिक मौका है, जिसका भारत ने भरपूर लाभ उठाया है। यह खाद भारत को उस कीमत पर मिली है, जिसके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अभी कोशिश ही कर रहे हैं। भारत की चार कंपनियां इंडियन पोटास लिमिटेड, राष्ट्रीय कैमिकल फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स और कृषक भारती कोऑपरेटिव रूस से इस खाद का आयात करेंगी।

मॉनसून की धीमी रफ्तार, 57 प्रतिशत जिलों में सामान्य से कम बारिश, प्रभावित हुई खरीफ फसलों की बुवाई

हलधन किसान। मॉनसून की शुरुआत को करीब एक एक महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक नियमित बारिश नहीं हुई, यही कारण है कि देश के 57 फीसदी जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने से इसका सीधा असर खरीफ की फसल बुआई पर पड़ा है। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 जून 222 को समाप्त सप्ताह तक पिछले साल के मुकाबले देश में 23.81 प्रतिशत खरीफ की बुआई कम हुई है।

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 से 27 जून 2022 के दौरान देश के 20 प्रतिशत (143) जिलों में सामान्य बारिश हुई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इसी साल मौसम विभाग ने सामान्य बारिश के आंकड़ों में भी कमी कर दी है। जून के अंतिम सप्ताह में मॉनसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन अभी भी 49 प्रतिशत (345) जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। 76 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। बारिश न होने के कारण अभी भी खरीफ की बुआई में बहुत अंतर नहीं आया है।

किन राज्यों में कैसी स्थिति

मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 30 जून को 12 राज्यों में सामान्य से बहुत अधिक और छह राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। लेकिन जिन राज्यों में अभी सूखा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उनमें मध्य भारत के महाराष्ट्र (सामान्य से 27 प्रतिशत कम), छत्तीसगढ़ (सामान्य से 27 प्रतिशत कम), गुजरात (सामान्य से 47 प्रतिशत कम), ओडिशा (सामान्य से 37 प्रतिशत कम), दादर नागर हवेली (सामान्य से 53 प्रतिशत कम) और मध्य प्रदेश (सामान्य से 15 प्रतिशत कम) शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले आंकड़े

चौंकाने वाले आंकड़े छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जून में 1.990 लाख हेक्टेयर में ही धान की बुआई हो पाई है, जबकि पिछले साल 2021 में जून में 6.610 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी, जबकि उससे पिछले साल यानी 2020 में 13.400 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में इस साल जून माह में 27 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कम बारिश का असर महाराष्ट्र पर भी देखा जा रहा है।

1 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अभी भी पिछले साल की तुलना में 15.70 लाख हेक्टेयर में कम बुआई हुई है। सबसे अधिक प्रभावित धान की फसल हुई है। पिछले साल के जून के मुकाबले इस साल 16.11 लाख हेक्टेयर (27.05 प्रतिशत) में बुआई कम हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में 1 जून से 1 जुलाई 2022 के दौरान सामान्य से केवल 6 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस स्थिति को सामान्य ही माना जाता है, लेकिन अभी भी जून माह में 15 राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि जून के आखिरी सप्ताह में हुई भारी बारिश की वजह से कई जिलों में आंकड़ा सामान्य से ऊपर चला गया।

उत्तर भारत में बारिश की कमी अभी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई तक सामान्य से 46 प्रतिशत कमए उत्तराखंड में सामान्य से 29 प्रतिशत कम, हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 48 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मॉनसून की बारिश के असर का आंकलन इस बात से लगाया जाता है कि खरीफकी बुआई कितनी हो चुकी है। जून माह के तीन सप्ताह लगातार खरीफ की बुआई प्रभावित हुई। लेकिन आखिरी सप्ताह जब कई राज्यों और जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई, बावजूद इसके खरीफ की बुआई प्रभावित हुई। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल जून माह के दौरान 294.42 लाख हेक्टेयर में खरीफकी बुआई हो चुकी थी, लेकिन इस साल जून माह में 278.72 लाख हेक्टेयर में बुआई हो पाई है। यानी कि अभी भी 15.70 लाख हेक्टेयर यानी 5.33 प्रतिशत बुआई कम हुई है।

आंकड़ों के मुताबिक अब तक धान की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले 27.05 प्रतिशत, अरहर का 13.80 प्रतिशत, कुल्थी का 37.41 प्रतिशत, उड़द का 8.92 प्रतिशत, ज्वार का 35.10 प्रतिशत, रागी का 49.88 प्रतिशत, मक्का का 13.87 प्रतिशत, मूंगफली का 24.98, सीशम 10.36 प्रतिशत कम रिकॉर्ड किया गया।

धान की बुआई पर असर

खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान है। सरकारी खरीद होने के कारण कई राज्यों में इसकी बुआई बहुत अधिक होती है और धान को बहुत अधिक पानी भी चाहिए होता है, इसलिए किसान मॉनसून में भारी बारिश का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन पूरा जून महीना बीतने के बावजूद किसानों को धान की बुआई के लिए बारिश का इंतजार खत्म नहीं हो पाया है। इस साल जून के महीने में 43.448 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है जो पिछले साल 2021 के मुकाबले 16.108 लाख हेक्टेयर कम है, जबकि 2020 के मुकाबले 31.142 लाख हेक्टेयर कम है। यही आंकड़े राज्यवार देखें तो इस साल जून में 15.750 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई थी, जो 2021 के जून माह के मुकाबले 8.020 लाख हेक्टेयर और 2020 के जून माह के मुकाबले 7.880 लाख हेक्टेयर कम है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जून माह में पंजाब के 22 जिलों में से सात जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। हालांकि पंजाब में सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण मॉनसून की बारिश न होन से कोई खास असर नहीं पड़ता है। हालांकि पिछले सप्ताह हुई बारिश की वजह से कई राज्यों में खरीफ सीजन की बुआई में बढ़ोतरी हुई है। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक शामिल हैं।

मोबाइल एप के जरिये किसान खुद कर सकेंगे अपनी फसल की गिरदावरी

खरगोन (हलधर किसान)। आयुक्त भू अभिलेख मप्र की ओर से इस वर्ष गिरदावरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई.तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत मैप आईटी के द्वारा सैटेलाईट से प्राप्त ईमेज के आधार पर किसान से सत्यापन कराते हुए गिरदावरी अभिलेखों में दर्ज की जाएगी। भू अभिलेख अधिकारी पवन वास्केल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पटवारियों को गिरदावरी करना होती थी परंतु अब किसान स्वयं अपने खेत की गिरदावरी कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें एमपी किसान एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। जिसमें सैटेलाईट इमेज के आधार पर फसल दिखाई जाएगी। यदि कृषक एप में दिखाई जाने वाली फसल से सहमत हैं, तो यह कर ओके करेंगे। इसके बाद फसल सर्वर पर अपलोड हो जाएगी।

नहीं लगाना पड़ेगा पटवारियों के चक्कर

कई किसान समर्थन मूल्य के दौरान होने वाले पंजीयन में परेशान होते नजर आते थे। पटवारियों ने भी गिरदावरी करने का विरोध किया। अब इस तरह की समस्या पैदा ना हो इसको लेकर एक मोबाइल एप तैयार किया गया है। जिसके जरिये किसानों को गिरदावरी के लिए न तो पटवारियों के चक्कर लगाने होंगे और न सर्वे में फसल का गलत आकलन होगा। किसान एप डाउनलोड करके खुद एप के माध्यम से सेटेलाईट के जरिये अपनी फसल की गिरदावरी कर सकेंगे।

जनता से संवाद करने पहुंचे सीएम बघेल ने खेत में चलाया हल, कहा- वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले समूहों को पुरस्कृत करेगी सरकार

हलधर किसान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटकोना, पाराडोल व मनेंद्रगढ़ पहुंचे। सीएम ने सीधे संवाद कार्यक्रम के दौरान गौठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों को पुरस्कृत करने की बड़ी घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक वर्मी कम्पोस्ट बेचने वाले समूह को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले तीन स्थान पर आने वाले समूह को भी पुरस्कृत किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में की। वो यहां के गांव पाराडोल में आयोजित भेंट.मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान खडगांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, छोटे कलुआ में बिजली सब स्टेशनए कौड़ीमार में स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की गई। सीएम ने कहा कि मैं जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन देखने आया हूं। जनप्रतिनिधि विधानसभा में योजना बनाते हैं तो अधिकारी उसको क्रियान्वित करते हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाने अधिकारियों को साथ लेकर आया हूं।

पाराडोल में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहूए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर उनका पारम्परिक स्वागत किया गया।

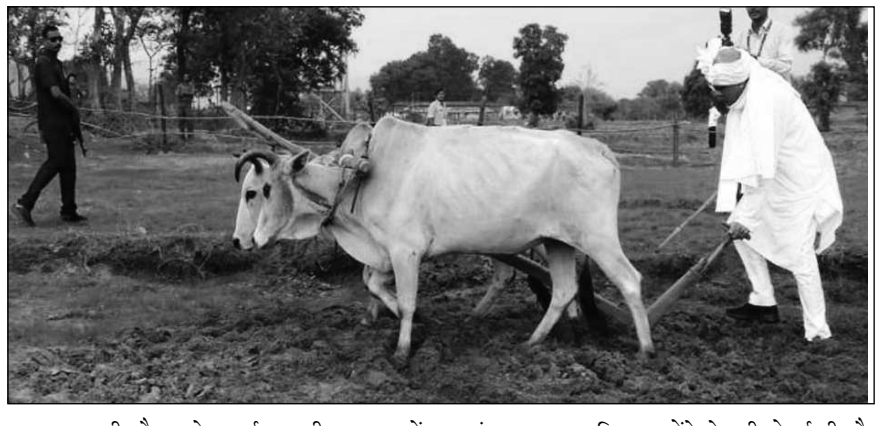

खुद हल चलाकर कि खेत की जुताई

सीएम ने ग्राम पंचायत पाराडोल में आम जनता से सीधे संवाद किया, इसके बाद गांव के कोटवार के खेत में पहुंचकर हल थाम लिया। उन्होंने खेत की जोताई की और बीज बोने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी से अच्छी फसल होने की मन्नत मांगी। इस दौरान गार्ड पहरा देते रहे और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें खेत जोतते देखते रहे। उन्होंने भोजन भी किसान के घर किया। किसान मनकेश्वर सिंह के घर दोपहर का भोजन किया। पारम्परिक व्यंजन बथुआ के सुक्सी भाजी, मुनगा सब्जी, तोरई सब्जी और लकड़ा चटनी का स्वाद लिया।

संपादकीय...

जल संरक्षणः स्थायी भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान

मानव जाति की स्थापना के बाद से हीं पानी प्रकृती का एक अनमोल वरदान रहा है। यही वजह है कि मानव जाति चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचकर पानी की तलाश में जुटी है ताकि यहां भी जीवन संभव हो सकेण् लेकिन धरता पर मौजूद पानी का स्तर लगातार कम होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मानव जाति की स्थापना के बाद से हीं पानी प्रकृती का एक अनमोल वरदान रहा हैण् यही वजह है कि मानव जाति चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचकर पानी की तलाश में जुटी है ताकि यहां भी जीवन संभव हो सके। लेकिन धरता पर मौजूद पानी का स्तर लगातार कम होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिसके बिना जीवन असंभव हैण्गौरतलब है कि हमारे शरीर में 70 प्रतिशत पानी होता है। यह एक ऐसा संसाधन है, जो अधिकतर पृथ्वी का निर्माण करता है, लेकिन फिर भी इसके कम होने का डर बना हुआ है। पानी हमारे लिए जितना जरूरी है उतनी ही आज इसकी बर्बादी हो रही है।

बढ़ती आबादी और पर्यावरण में हो रहे बदलाव के चलते धरती पर पानी की कमी होती जा रही हैण् और ये कमी भविष्य में बहुत बड़ी समस्य बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर फसलों से लेकर सभी जीव जंतुओं तक पर पड़ रहा है। पानी की कमी की वजह से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है जिसके चलते मानसून की चाल से लेकर बारिश का पैटर्न तक लगातार बदल रहा है। कई जगह अचानक सूखा और फिर बाढ़ आम होती जा रही है। जब ऐसा होता है तो अधिकांश पानी बह जाता है और जिसकी वजह से जल का संग्रह नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं लगातार भूमिगत जल का स्तर भी कम हो रहा है। ऐसा देखा गया है कि कई जगह बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो कई जगह बहुत कम होती है। इस साल भी ऐसा ही देखने को मिला। जिसके चलते अगस्त / सितंबर में फसल का काफी नुकसान हुआ। इसलिए जब तक किसान बारिश के पानी का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक वे इस तरह की समस्य से जूझते रहेंगे।

पानी का कमी न केवल जीवन को प्रभावित कर रही है बल्कि पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इसका मतलब साफहै कि अगर धरती पर पानी की कमी होगी तो फसलों से ठीक उत्पादन नहीं लिया जा सकता जिससे हमारे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था सीधे.सीधे प्रभावित होगी। आपको बता दें कि पानी का जो सरप्लस है उस पर कब्जा करके पानी का संरक्षण करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

खेतों में तालाब बनाकर भी पानी को संरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी (एक गैर.लाभकारी संगठन) ने झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में 800 तालाबों का निर्माण किया है, जिससे न केवल सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी मिल रहा है। बल्कि मछली पालन के जरिए कमाई के नए विकल्प भी खुले हैं। इसी तरह यहां विशेषीकृत लाइनिंग भी उपलब्ध हैं जो कि एल्गी के विकास में मदद करते हैं और बेहतर मछली पालन के लिए मछली पालन के जरिए कमाई के नए विकल्प भी खुले हैं। इसी तरह यहां विशेषीकृत लाइनिंग भी उपलब्ध हैं जो कि एल्गी के विकास में मदद करते हैं और बेहतर मछली पालन के लिए एक प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं।

अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो जल संरक्षण के लिए कई तरीखों को अपनाया जा सकता है। इनमें से कुछ बहुत है अहम है। इनमें से ड्रिप सिंचाई एक अच्छा विकल्प हैण् ड्रिप सिंचाई का रुख करना और आधुनिक उपाय जैसे कि आईओटी सेंसर और कम्प्यूटरीकृत सिस्टम को अपनाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन ऐसे उत्पादों को अधिक सुलभ और सस्ता बनाने की जरूरत है। चूंकि ग्रामीण भारत फसल की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है। ऐसे में जल प्रबंधन सिर्फलोगों की प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था और सभी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह दुनिया के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने और किसानों को पानी की कमी के विनाशकारी प्रभावों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रतियां पाने, लेख प्रकाशन के लिए संपर्क करें

हलधर किसान, राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र की प्रतिया प्राप्त करने के लिए अपना नाम, डाक पता और फोन नंबर सहित संपर्क करें। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, शोध, खेती में नवाचार जैसे लेख प्रकाशन कराना चाहते है तो हमें वाट्सएप नंबर- 8305103633, 94254 89337 पर भेजे सकते है। हम आपका लेख प्रमुखता से फोटो सहित उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे।

छह राज्यों में बंद हुई चने की सरकारी खरीद, अब खुले बाजार में गिरे दाम, एमएसपी से कम मिलने लगे भाव

हलधर किसान। सरकार द्वारा तय लक्ष्य का करीब 88 फीसदी समर्थन मूल्य पर चना खरीदा जा चुका है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सरकारी खरीद अब बंद हो चुकी है। खरीद बंद होने का असर अब खुले बाजार में दाम गिरने लगे है। शासकिय खरीदे में जहां 5230 रुपए के भाव मिल रहे थे वहीं अब खुले बाजार में भाव सिर्फ 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल तक ही मिल रहा है। चने के सबसे बड़े उत्पादक मध्य प्रदेश के बाजारों में भी इसका दाम एमएसपी से कम ही मिल रहा है।

नेफेड ने 29 जून तक चने की कुल 25.76 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है। जबकि उसके पास तकरीबन 32 लाख मीट्रिक टन चने का स्टॉक पड़ा हुआ है। जिसमें से 6.24 लाख मीट्रिक टन का पुराना स्टॉक है। दलहन फसलों में चने की भागीदारी करीब 45 प्रतिशत है। इसके सबसे बड़े उत्पादक एमपी में ही सबसे ज्यादा सरकारी खरीद भी हुई है।

किस राज्य में कितनी हुई चने की खरीद

राज्यवार सरकारी खरीद के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 7.60 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा गया।

गुजरात में 5.59 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद हुई है।

मध्य प्रदेश में 8.02 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा गया है।

राजस्थान में 2.85 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है।

कर्नाटक में 74 हजार मीट्रिक टन चने की खरीद हुई है।

आंध्र प्रदेश में 72 हजार मीट्रिक टन चना खरीदा गया है।

उत्तर प्रदेश में 19.56 हजार मीट्रिक टन चने की सरकारी खरीद हो चुकी है।

कहां कितना था चना खरीद का लक्ष्य

महाराष्ट्र में चने की सरकारी खरीद का लक्ष्य 7.76 लाख मीट्रिक टन था। गुजरात में 5.36 लाख मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 8.71 लाख मीट्रिक टन और राजस्थान में 5.98 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया था।

अगर देश भर में चने के उत्पादन की बात करें तो इसे सालाना आधार पर 17.4 फीसदी बढ़कर 139.8 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। गुजरात में चना उत्पादन 49 फीसदी बढ़कर 21.4 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। राजस्थान में चना उत्पादन 20 फीसदी बढ़कर 27.2 लाख मीट्रिक टन और महाराष्ट्र में 15 फीसदी बढ़कर 27.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है।

कहां-कितना चने का उत्पादन

दलहन फसलों में अहम स्थान रखने वाले चने की सरकारी खरीद अब अंतिम चरण में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खरीद बंद हो चुकी है। केंद्र ने 2022.23 के लिए 29 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का लक्ष्य रखा था। तय किए गए लक्ष्य के करीब 88 फीसदी चना खरीदा जा चुका है रबी मार्केटिंग सीजन 2022–23 में सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (5230 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था)

मंडियों में कितनी हुई आवक

ओरिगो ई.मंडी की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च से 29 जून 2022 के दौरान मंडियों में चने की आवक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 16.9 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई है। इस साल मार्च महीने के दौरान आवक 21 फीसदी कम दर्ज की गई थी। हालांकि अप्रैल के बाद से इसमें बढ़ोतरी हुई। अब तक सालाना आधार पर आवक में 17 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

31 जुलाई तक करा सकते हैं फसलों का बीमा

हलधर किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। कृषि उपसंचालक एमएल चौहान ने बताया कि यह तिथि ऋणी और अऋणी किसानों के लिए हैं। अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केंद्र या फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी करा सकते है। जबकि ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार ने फसल बीमा योजना को ऐच्छिक किया गया है। प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसान जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं वे बीमे की अंतिम तिथि से 2 दिन पूर्व 29 जुलाई तक सम्बंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं।

अधिसूचित फसलों में सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग, और उड़द की फसलों को शामिल किया गया है। कपास की फसल को छोड़कर अन्य अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की राशि किसानों को भरना होगी। जबकि कपास की फसल के लिए किसानों को अधिकतम 5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम भरना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जरूरी है।

42 लाख से अधिक 'गलत खातों' में गए, 4350 करोड़ प्लस रुपये, सरकार ने की वसूली की तैयारी

हलधर किसान (नई दिल्ली)। पीएम किसान सम्मान निधि में 42 लाख से अधिक 'गलत लाभार्थियों' को 4350 करोड़ से अधिक पैसे मिलने का मामला उजागर हुआ है। योजना की शुरुआत दिसंबरए 2018 में की गई। इस योजना से करोड़ों किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार की ओर से 2000 रुपये की किस्त जमा की जाती है। 12 महीनों में कुल 6000 रुपये जमा होते हैं।

उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक किसानों को अपात्र माना गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपात्र लाभार्थियों से वसूली कर रही है। महाराष्ट्र के रायगड में 26 हजार से अधिक किसान अपात्र पाए गए हैं। बता दें कि गत 11 मई को टाइम्सऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ तीन लाख टैक्स भरने वाले लोगों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस स्कीम का गलत लाभ लेने वाले लोगों से 200 करोड़ रुपये की वसूली किए जाने की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के चीफसेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अवैध लाभार्थियों से वसूली का निर्देश दिया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि देशभर में लगभग 42.73 लाख लोगों को पीएम किसान योजना का पात्र नहीं पाया गया, लेकिन इन लोगों के बैंक खातों में पैसे जमा हुए। इन लोगों को पैसे लौटाने ही होंगे। कृषि मंत्रालय ने तय किए हैं व्च् रिपोर्ट में कहा गया कि नियमों के मुताबिक जिन श्किसानों को योजना के तहत पैसे मिले हैं, लेकिन वे इसके पात्र नहीं थे, इन लोगों को स्वेच्छा से पैसे लौटाने होंगे। ऐसा न करने पर सरकार रिकवरी प्रोसिडिंग शुरू करेगी। नियमों के तहत राज्य सरकार इन अपात्र किसानों से पैसों की वसूली करने के बाद केंद्र सरकार के अकाउंट में पैसे जमा कराएगी। वसूली के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से मानक प्रक्रिया तय की गई है। क्या चुनाव के कारण नोटिस नहीं भेजे गए? खबरों के मुताबिक वसूली के नोटिस भेजने में देरी का एक प्रमुख कारण वोटबैंक रहा है।

हिंदुस्तानटाइम्स डॉटकॉम की रिपोर्ट में कहा गयाए किसानों के आंदोलन और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक होने के कारण राज्य सरकार के अधिकारियों ने पीएम किसान स्कीम के अपात्र लाभार्थियों को नोटिस भेजने से परहेज किया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित कराए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया था। केंद्र सरकार के अधीन हैं राज्य हिंदुस्तानटाइम्स डॉटकॉम की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के हवाले से कहा गया, पीएम किसान की किस्तों की वसूली का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। नाम न छापने की अपील कर मंत्री ने बताया सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि केवल पात्र किसान ही पीएम.किसान स्कीम का लाभ उठाएं। राज्य सरकार को केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार ही काम करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11 किस्तें किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुकी है।

योजना के मकसद को झटका !

इसी रिपोर्ट में एडिशनल चीफसेक्रेटरी (एग्रीकल्चर) देवेश चतुर्वेदी के हवाले से कहा गया कि गलत लोगों के बैंक खातों में पैसे जाने के कारण कम आमदनी वाले किसानों की मदद के लिए शुरू हुई पीएम किसान सम्मान निधि के मकसद को झटका लगा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इन किसानों से जल्द से जल्द पूरी रकम वसूल करेगी। 42.73 लाख लोग योजना के पात्र नहीं इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि पर 9 जनवरी 2022 को प्रकाशित हिंदुस्तानटाइम्स डॉटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने यूपी में अक्टूबर, 2021 तक करीब 7.23 लाख किसान पीएम किसान योजना के लिए अयोग्य पाया।

फर्टिलाइजर पर जीएसटी सिर्फ 5 प्रतिशत तो कीटनाशकों पर 18 फीसदी क्यों?

11वें एग्रोकेमिकल्स सम्मेलन में फिक्की ने उठाए सवाल

हलधर किसान। नई दिल्ली में एक समृद्ध कृषि रसायन उद्योग के लिए पॉलिसी लैंडस्केप विषय के साथ अपने 11वें एग्रोकेमिकल्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इसमें फिक्की की क्रॉप प्रोटेक्शन कमेटी ने कीटनाशकों पर जीएसटी परिषद से मांग की है कि कृषि रसायनों (कीटनाशकों) पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य या अधिकतम 5 प्रतिशत करने की संभावना पर विचार करे।

फिक्की द्वारा आयोजित पॉलिसी लैंडस्केप फॉर ए फ्लोरिशिंग एग्रोकेमिकल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिक्की की फसल सुरक्षा समिति के प्रमुख और धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरजी अग्रवाल ने कहा कि इन रसायनों पर जीएसटी से छोटे और सीमांत किसानों की इनपुट लागत में वृद्धि होती है। कृषि.रसायन पर 18 प्रतिशत का जीएसटी अनुचित है क्योंकि वे न केवल फसल सुरक्षा के लिए बीमा के रूप में कार्य करते हैं बल्कि उनकी गुणवत्ता, उपज और आय में भी वृद्धि करते हैं। 18 प्रतिशत की यह उच्च दर उचित नहीं है। इसे या तो शून्य होना चाहिए या उर्वरकों के बराबर अधिकतम 5 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए।

अग्रवाल ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए मॉलिक्यूल्स के पंजीकरण मे तेजी लाने के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति(सीआईबी और आरसी) में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि

यह भ्रम है कि भारत में किसान कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल करते हैं। सच तो ये है कि चीन के मुकाबले भारत में प्रति हेक्टेयर बहुत कम कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता है।

पूर्व कृषि आयुक्त डॉ चारूदत्त दिगंबर माई ने कहा कि कृषि रसायन उद्योग हमारे किसानों के लिए काम करता है और फसल के नुकसान को कम करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ उच्च उपज का आश्वासन देता है। केंद्र सरकार को कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तत्काल मजबूत मशीनरी स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह किसानों के साथ.साथ मिट्टी के लिए भी अच्छा होगा। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी एंड आरसी) में सुधारों की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, यह सरकार द्वारा नए अणुओं के पंजीकरण में तेजी लाने की दृष्टि से किया जाना चाहिए जो किसानों की उपज और आय की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार द्वारा नियामक निर्णयों के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन से कृषि क्षेत्र को स्थाई रूप से लाभ पहुंचाने वाले समाधान को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने कीटनाशक को एक चैंपियन सेक्टर घोषित किया है और इसलिए विकसित देशों से नई तकनीक और निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से भारत के कानूनों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के साथ सामंजस्य बिठाना आवश्यक है। इसलिए ड्राफ्ट पीएमबी 2020 के प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, जो कोविड से पहले तैयार किया गया था।

केंद्र सरकार की 5 प्रमुख योजनाओं का समय रहते लाभ उठाए किसान

हलधर किसान। केंद्र सरकार की कई जनहितैषी योजनाओं में 5 प्रमुख सरकारी योजनाएं ऐसी है जिसका किसान सीधे लाभ उठा सकते है।.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनधन योजना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट या खराब होने वाली अपनी फसल की भरपाई के लिए सरकारी सहायता राशि का लाभ ले सकें। कभी बाढ़, कभी अकाल तो कभी आंधी.तूफान या ओलावृष्टि आदि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में किसान सहायता के लिए सरकार की ओर ताकता है। किसानों के इस दर्द को महसूस करते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लांच की। इसमें फसल की बुआई के पहले चक्र से लेकर फसल की कटाई के बाद तक का चक्र शामिल होता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना–किसानों के लिए सबसे लाभदायक योजना है किसान सम्मान निधि योजना। इसके कई फायदे हैं। इस योजना में किसान को साल में छह हजार रुपये की सहायता राशि बतौर किसान सम्मान निधि उनके खातों में भेजी जाती है। यह राशि तीन किश्तों में दी जाती है। इसके लिए किसान को ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है। वहीं किसान होने के प्रमाण के तौर पर जमीन के कागजात जरूरी होते हैं। किसान सम्मान निधि के लिए सरकार ने आवश्यक पात्रता निर्धारत की है। इसके लिए छह हेक्टेयर जमीन का होना जरूरी है। इसके अलावा बंटाई किसानों के लिए हिस्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि शामिल है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कम ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया जाता है। इसकी शुरूआत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने की थी। अब यह किसान क्रेडिट कार्ड को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। केसीसी के माध्यम से किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण भी प्रदान किया जाता है। इसमें 3 लाख रुपये तक का लोन 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना– केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में किसानों और आमजन के लिए एक अन्य योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह योजना गरीब व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ने और इन्हे बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। इसमें जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है। यह खाता बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। योजना के तहत खाताधारक को 1.30 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा आपको दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण– आज भी अनेक लोगों के पास अपना घर नहीं है। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र ऐसे देश में लाखों लोग हैं जिन्हे आशियाने की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई व्यक्ति बिना छत के नहीं रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की है। यह शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के निवासियों के लिए लाभदायक है। यहां आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में रहने वाले उन लोगों को घर उपलब्ध कराना है जो बेघर हैं। गौरतलब है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनो ही क्षेत्रों के गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की महती योजना है।

देवनारायण आवास योजनाः राजस्थान के कोटा बने आधुनिक आवासों में 501 लाभार्थियों को कराया गृह प्रवेश

स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी पशुपालकों के लिए ऐसी कोई योजना देखने को नहीं मिलेगी

हलधर किसान। राजस्थान सरकार ने राज्य के पशु पालकों के लिए एक अनूठी योजना शुरू की थी जिसके तहत पशुपालकों के लिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना के तहत एक अलग से कस्बा बनाया गया है। इस कस्बे में पशुपालकों को अत्याधुनिक सुविधाओं के घर वितरित किए गए है। देशभर में अनूठी एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पशुपालकों के लिए पहली बार तैयार की गई कॉलोनी का स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कब्जा सौंपकर लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया।

पशुपालकों के लिए दुनिया में पहली हाईटेक आवासीय योजना राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी पशुपालकों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित ऐसी कोई योजना देखने को नहीं मिलेगी, जहां एक साथ पशुपालकों को बसा कर उनका शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए जिस तरह से पशुपालक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे अब उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आयेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में जिस प्रकार आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है उसको देखने देश.दुनिया के शिल्पकार आयेंगे। इसमें पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ कोटा शहर को पशु दुर्घटना से मुक्त होने में मदद मिलेगी।

स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि भगवान देवनारायण के नाम पर पहली योजना है जो सरकार द्वारा आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित की गई है। इसमें वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ पशुपालकों के बच्चों के भविष्य के लिए भी प्रावधान किये गये हैं। पशु पालकों के लिए बनाई गई इस परियोजना में अंग्रेजी माध्यम स्कूल, चिकित्सालय, दुग्ध मंडी, हाट बाजार, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, बायोगैस प्लांट, आवागमन के लिए बसों का संचालन जैसी सुविधाओं से पशुपालकों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास को पूरा किया जा सकेगा।

क्या है देवनारायण आवासीय योजना की विशेषताएं

योजना में पशुपालकों के लिए 1227 बड़े आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया है। इनमें से 738 आवासों का निर्माण पूर्णकर 501 पशुपालकों को आवंटन कर दिया गया है। इन भूखंडों के पिछले भाग में लगभग 40 वर्ग मीटर क्षेत्र में दो कमरे, रसोईघर, शौचालय, स्नानघर, बरामदा, चारा भण्डारण की सुविधा है।

भूखंड के अग्रभाग में पशुओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है। जिसमें भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार 18 से 28 पशुओं के पालने की क्षमता होगी। इस योजना में आवासीय भूखंडों के अतिरिक्त डेयरी उद्योग के लिए 50, भूसे गोदाम के 14ए खलचुरी व सामान्य व्यवसाय के लिए 112 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। पशुपालकों की सुविधा के लिए योजना में विद्यालय भवन, पशु चिकित्सालय, सोसाइटी कार्यालय, पुलिस चौकी विद्युत सब स्टेशन, पेयजल के लिए उच्च जलाशय, सीवर लाइन, पार्क, नाली, सड़कें, एसटीपी, पशुमेला मैदान एवं दुग्ध मण्डी का भी निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच का निर्माण किया गया है।

पशुपालकों से ख़रीदा जाएगा गोबर

योजना में लगभग 15 हजार पशुओं से प्राप्त गोबर के निस्तारण के लिए नगर विकास न्यास द्वारा बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। बायोगैस संयंत्र की स्थापना से इस योजना को गोबर की दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी तथा पशुपालकों से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बायोगैस संयंत्र के लिए गोबर खरीदा जाएगा। बायोगैस से उत्पन्न गैस को पाइप लाइन के माध्यम से घरों में सप्लाई किया जायेगा। बायोगैस संयंत्र से गोबर के निस्तारण के साथ.साथ जैविक खाद का भी उत्पादन होगा। 2020 में की गई थी योजना की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में 300 करोड़ रुपये की लागत से कोटा शहर के पशुपालकों को सुव्यवस्थित रुप से बसाने के लिए देवनारायण एकीकृत आवास योजना विकसित करने की घोषणा की गई थी। परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त 2020 को रखी गई। जिसमें नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रथम चरण में 738 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 501 आवासों का आवंटन किया।

देशभर के 63000 पैक्स का होगा कंप्यूटरीकरण, मोदी केबिनेट ने 2500 करोड़ के प्रावधान को दी मंजूरी

हलधर किसान। केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र में बदलाव की योजना पर काम कर रही है। हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशभर में फिलहाल कार्यरत करीब 63000प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण का फैसला किया गया। इसके लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक हर पैक्स को इस काम के लिए करीब 4 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार का होगा।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले से लगभग 13 करोड़ छोटे व सीमांत किसान लाभांवित होंगे और इस डिजिटल युग में कंप्यूटरीकरण का निर्णय इनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। पैक्स के कार्य क्षेत्र में व्यापक विस्तार किया गया है। इसके लिए बैंक मित्र भी काम करेंगे। पैक्स के अधीन कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृहए, लॉकर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानेंए एफपीओ, दुग्ध एवं शहद उत्पादन और मत्स्य पालन, नल से जलए सिंचाई व्यवस्था भी होगा।

कंप्यूटरीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाने के साथ उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है। इससे पैक्स की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। साथ ही बहुउद्देश्यीय पैक्स की अकाउंटिंग में भी सुविधा होगी। पैक्स देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर की इकाई है जो ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देती है। करीब 13 करोड़ किसान इसके सदस्य हैं और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की एक अहम कड़ी साबित हो सकती हैण् इसके महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर पैक्स में 5.10 लोगों को रोजगार देने की क्षमता होती है।

2.516 करोड़ के खर्च को मंजूरी

इस बीच कैबिनेट ने पहले से चल रही 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण व बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए 2.516 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है। देशभर में पैक्स के एक समान कामकाज के लिए राज्यों की सहमति से इसके मॉडल बदलाव करने के लिए नया बाईलाज लागू किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 फीसदी

देश में सभी संस्थाओं की तरफ से दिए गए केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) है। पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में से 95 प्रतिशत (2.95 करोड़ किसान) छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि 2024 तक तीन लाख पैक्स के गठन के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि देशभर में पैक्स को एक सफ़ल आंदोलन बनाने के लिए एक मॉडल क़ानून बनाया जा रहा है जिससे पैक्स का कामकाज पूरे देश में एक समान चल सकेगा। इस मॉडल कानून को जल्द ही राज्यों के साथ साझा किया जा सकेगा ताकि राज्य इसे लागू कर सकें। संविधान के मुताबिक सहकारिता का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है लिहाज़ा केंद्र सरकार सीधे तौर पर क़ानून नहीं बना सकती।

मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र में लगातार बदलाव की तैयारी कर रहा

इस मॉडल कानून में पैक्स के कामकाज को और विस्तार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इनमें बैंक मित्र बनानेए कोल्ड स्टोरेज चलाने, सरकारी राशन की दुकान चलाने और कॉमन सर्विस सेंटर चलाने जैसे काम शामिल किए गए हैं। वर्तमान क़ानूनी प्रावधान पैक्स को ऐसे अन्य काम करने की इजाज़त नहीं देते हैं। पिछले साल ही सहकारिता विभाग को कृषि मंत्रालय से हटाकर एक नए मंत्रालय के तौर पर स्थापित किया गया और गृह मंत्री अमित शाह को इसका मंत्री बनाया गया तभी से मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र में लगातार बदलाव और सुधार की तैयारी कर रहा। इसी क्रम में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन क़ानून 2002 में भी बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक़ जल्द ही इसका मसौदा जारी किया जाएगा। कानून में बदलाव का उद्देश्य बड़े बड़े कोऑपरेटिव इकाइयों में आधुनिकीकरण और पारदर्शिता लाना है। ऐसी करीब 1300 इकाइयां देश में कार्यरत हैं जिनमें बड़ी संख्या महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में हैंद्ध इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय सहकारिता नीति और एक सहकारिता विश्वविद्यालय के गठन की भी योजना बना रही है। सहकारिता नीति में सहकारिता क्षेत्र में निवेश और इज ऑफडूइंग बिजनेस से जुड़े विषय शामिल किए जाएंगे।

पैक्स को पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा

पैक्स को पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा। पैक्स में डाटा स्टोरेज के साथ साइबर सुरक्षाए मौजूदा अभिलेखों का डिजिटलीकरण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से करोड़ों किसानों को फायदा होगा। यह फैसला खासकर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।–. ***नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री***

खरीफ सीजन में किसानों न आए पैसे की कमी, यूपी सरकार दे रही 63 हजार करोड़ रुपए का लोन

हलधर किसान। खरीफ फसलों से अधिक पैदावार लेने में पैसे की कमी किसानों के आड़े न आए, इसके लिए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार पिछले सीजन के मुकाबले 40 प्रतिशत अतिरिक्त लोन का वितरण करने जा रही है। बीते साल खरीफ सीजन से पहले किसानों के बीच 45,000 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया था। इस बार राशि को बढ़ाकर 63.000 करोड़ कर दिया गया है।

कृषि विभाग ने खरीफसीजन में पारंपरिक फसलों की खेती पर एक अध्ययन किया है, उसी के आधार पर निर्णय लिया गया है कि किसानों को अधिक संसाधन मुहैया कराया जाए ताकि प्रति हेक्टेयर उपज में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही विभाग की योजना है कि किसान गुणवत्तापूर्ण बीज का चुनाव कर खेती करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। हर पांच साल पर कृषि विभाग नई किस्म के बीजों को किसानों के बीच पहुंचाता है ताकि वे इन किस्मों की खेती कर फायदा ले सकें।

क्षेत्र में बढ़ रहा है उड़द का रकबा

कृषि उत्पादन कमिश्नर मनोज कुमार सिंह ने अपने अध्ययन में पाया है कि एक ही क्षेत्र के कुछ जिलों में खरीफफसलों की पैदावार में भारी अंतर है। टाइम्स ऑफइंडिया की एक रिपोर्ट में इस स्टडी के हवाले से कहा गया है कि बुंदेलखंड के जिलों ललितपुर और जालौन में उड़द के उत्पादन में बड़ा अंतर है, जालौन में उड़का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 15.50 क्विंटल है तो ललितपुर में यह महज 2.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

जालौन के प्रगतिशील किसान गौरव पांडेय ने बताया कि बुंदेलखंड का क्षेत्र सूखाग्रस्त है। गन्ना और धान जैसी अत्यधिक पानी की जरूरत वाली फसलों की खेती करना यहां पर कठिन है। बीते 5.6 वर्षों में यहां पर उड़द की खेती का चलन बढ़ा हैण् इसके पीछे की वजह सरकार की कोशिशें ह। कृषि विभाग की तरफ से उच्च सब्सिडी पर किसानों को उड़द का बीज मुहैया कराया जाता है।

बिहार में तरबुज के पल्प से बनाया जा रहा है गुड

हलधर किसान। अगर आप गुड खाने के शौकिन हैं तो जल्द आपको नए तरीके से बना गुड़ खाने को मिलेगा। अब तक आपने गन्ने के रस, नारियल और खजूर से बना गुड़ खाया होगा। अब तरबूज से गुड़े का स्वाद भी चखने को मिलेगा। इसे बड़ा ही फायदेमंद बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए ये गुणकारी होगा।

बिहार के समस्तीपुर के पूसा स्थित डा.राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानियों ने यह अनुसंधान किया है। हालांकि अभी तक इसे ठोस रूप देने में सफलता नहीं मिली है। वैज्ञानिकों ने तरबूज से तरल गुड़ बनाने में सफलता पाई है।

1 हजार किलो में 80.90 किलो तैयार हो रहा तरल गुड़

ईख अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ.ए के सिंह ने बताया कि तरबूज में बीज अलग कर पल्प की पेराई के बाद जूस को बायलर टैंक में भेजा जाता है। वहां इसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करने पर यह

गाढ़ा तरल बन जाता है। एक हजार किलो तरबूज में करीब 80 से 90 किलोग्राम तरल गुड़ तैयार हो रहा है।

अभी गुड़ को ठोस आकार देना बाकी

वैज्ञानिकों को अभी इसे ठोस आकार देने में सफलता नहीं मिली है। सिंह ने बताया कि तरबूज से गुड़ बनाने पर शोध की शुरुआत पिछले वर्ष जून में हुई थी। विभिन्न स्तरों पर जांच के बाद गुड़ बनाने में सफलता मिली। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि यह मधुमेह के मरीजों के लिए भी लाभप्रद होगा।

तरबूज से बनाया जा रहा है मुरब्बा

विश्वविद्यालय में तरबूज के छिलके और पल्प के बीच मौजूद सफेद हिस्से से मुरब्बा भी तैयार किया जा रहा हैण् बिहार में 4.60 हजार हेक्टेयर भूभाग में तरबूज की खेती होती हैण् गर्मी मौसम के प्रारंभ में तरबूज की कीमत अच्छी मिलती हैए लेकिन बारिश के मौसम में इसके मूल्यों में काफी गिरावट आ जाती है।

मानसून में हल्दवानी वन विभाग का 14.38 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य, 57.96 हेक्टेयर वनभूमि पर तैयार होगा बांस का जंगल

हलधर किसान। मानूसन की शुरुआत के साथ उत्तराखंड, नैनीताल वन विभाग का पौधारोपण अभियान भी शुरू हो जाएगा। वेस्टर्न सर्किल की डिवीजनों में 14.38 लाख पौधे लगाए जाएंगे। रेंज स्तर से लक्ष्य का आकलन करने के बाद 2119.06 हेक्टेयर जमीन का चयन हो चुका है। तराई केंद्रीय डिवीजन की 57.96 हेक्टेयर वनभूमि पर बांस का जंगल भी तैयार होगा।

विभाग के मुताबिक रोहिणी के बाद बांस हाथी के पसंदीदा भोजन में से एक है। बांस की भरपूर मात्रा में उपलब्धता होने पर हाथियों का आबादी की तरफआने का सिलसिला भी कम होगा। वन विभाग हर साल मानूसन के आने पर पौधारोपण अभियान भी शुरू करता है। रेंज स्तर पर जमीन ढूंढने के बाद संख्या का निर्धारण किया जाता है। वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त कार्यालय के मुताबिक बहुद्देश्यीय वनों का संरक्षण और कैंपा परियोजना का लक्ष्य अलग है। कुल मिलाकर 1438058 पौधे इस सीजन में रोंपे जाएंगे।

इसमें स्थानीय प्रजातियों के अलावा मिश्रित जंगल को भी तवज्जो दी जाएगी। तराई की कुछ डिवीजन में इमारती इस्तेमाल की प्रजाति भी मिलेगी। इसके अलावा आंवलाए जामुन, बेल, हरड़, बहेड़ा आदि को लगाकर वन्यजीवों के भोजन की उपलब्धता को और बढ़ाने का प्रयास होगा। तय समय में लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी श्रमिक जुटाए जाएंगे।

रामनगर डिवीजन में प्राकृतिक जंगल, प्लांटटेशन नहीं

वेस्टर्न सर्किल के तहत आने वाला रामनगर वन वन प्रभाग ऐसी डिवीजन है। जहां प्लांटटेशन के तौर पर एक भी पौधा नहीं रोका जाएगा। डीएफओ सीएस जोशी ने बताया कि यह डिवीजन प्राकृतिक और घने जंगल के जानी जाती है। इसलिए पिछले

साल की तरह इस बार भी प्लांटटेशन नहीं होगी। वहीं, अन्य डिवीजनों के मुकाबले इस डिवीजन का क्षेत्रफल भी कम है।

जुलाई में ही लक्ष्य पूरा करने की कोशिश

वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त दीप चंद्र आर्य ने बताया कि कोशिश रहेगी कि जुलाई माह में ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। रेंज स्तर तक लक्ष्य तय हो चुके हैं। पौधरोपण को लेकर सभी डिवीजनों में पूरी तैयारी है। स्थानीय के अलावा मिश्रित वन को तरजीह दी जाएगी। ताकि पर्यावरण संतुलन भी बना रहे।

डिवीजन वार आंकड़ा

डिवीजन	हेक्टेयर क्षेत्र	पौधों की संख्या
हल्द्वानी वन प्रभाग	209हे.	198700
तराई केंद्रीय प्रभाग	725.99 हे.	504075
तराई पूर्वी प्रभाग	831.50 हे.	511750
तराई पश्चिमी प्रभाग	352.57 हे.	223533

एमपी के इंदौर में 8 लाख पौधे रोपने का रखा लक्ष्य

शहर और जंगल में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग ने मानसून आते ही पौधारोपण का काम शुरू कर दिया है। इंदौर वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पौधारोपण शहरी क्षेत्र को पहली प्राथमिकता में रखकर किया जा रहा है। जिसके लिए नर्सरियों में 50 प्रजातियों के करीब 10 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक वनमंडल ने अप्रैल में ही पौधारोपण से जुड़े कार्य पूरे कर दिए हैं, जिसमें गड्ढे खोदाई, मिट्टी, खाद की व्यवस्था, मिट्टी परीक्षण, पौधारोपण स्थल पर फैंसिंग सहित अन्य कार्य शामिल हैं।

8 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य

डीएफओ नरेंद्र पंड्या ने बताया कि हमनें 8 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। जिसमें शहरी क्षेत्र को पहली प्राथमिकता दी है। यहां पर कॉलेज और स्कूलों में पौधा रोपण किया जाएगा। वहीं चोरल. महू रेंज में तीन. तीन और मानपुर और इंदौर में दो. दो लाख पौधे लगेंगे। वहीं सीड बाल भी जंगल में डालेंगे। प्रत्येक रेंज को दो. दो लाख सीड बाल का लक्ष्य रखा है।

नर्सरी में 10 लाख पौधे हुए तैयार

वन विभाग ने पौधारोपण के लिए नर्सरियों में पहले से ही 10 लाख पौधे तैयार करा लिए है। विभाग ने नर्सरी में आम, जाम, बबूल, बरगद, करंज, अंजनए सागवान, पारसपीपल, जामुन, पीपल, नीम सहित अन्य 50 प्रजातियों के पौधे तैयार कराए है। विभाग ने पौधे नवरत्नबागए रेंसीडेंसीए शोध व अनुसंधान केंद्रए मल्हाराश्रम की नर्सरी से तैयार कराए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पौधे इंदौर, महू, मानपुर और चोरल के 35 स्थानों पर रोपे जाएंगे। 15 जुलाई तक पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाबः कृषि विभाग में 1.178 करोड़ के घोटाले में ईडी की जांच शुरू, सरकार ने दिए दस्तावेज तैयार रखने के आदेश

हलधर किसान। पंजाब में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि विभाग में फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी से जुड़े 1.178 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने मामले में कृषि अधिकारियों को घोटाले से संबंधित रिकॉर्ड के साथ तैयार रहने के लिए कहा है।

सरकार ने एक विभाग को लिखे एक पत्र में कहा है कि ईडी जल्द कभी भी निरीक्षण कर सकता है। सरकार ने पत्र में कहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन (सीआरएम)

कागजों में आई मशीनें, हवा में किया पराली प्रबंधन

और कृषि मशीनीकरण (एसएमएएम) योजनाओं से संबंधित पूरे रिकॉर्ड की तीन प्रतियां विभाग को संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय इसकी आवश्यकता हो सकती है।

कागजो पर आई मशीनें

द ट्रिब्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बठिंडा में 34 कृषि मशीनरी बैंक 80 प्रतिशत केंद्रीय सब्सिडी की मदद से स्थापित किए जाने थे, लेकिन कृषि मशीनरी बैंक केवल कागजों पर ही रह गए। पिछली कांग्रेस सरकार समय पर कार्रवाई करने में विफल रही थी और यह घोटाला अगले तीन वर्षों तक जारी रहा। जब इस मामले को तूल पकड़ लिया तो पिछली सरकार ने इसे छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब के पूर्व कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर में अपनी ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान हुए फसल अवशिष्ट मशीनरी से जुड़े 1.178 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का पर्दाफाश किया था। उन्होंने पीएम से इसकी सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की थी।

राज्य सरकार को मिले थे 1178 करोड़

नाभा ने दावा किया था कि मशीनरी खरीदने के लिए चार साल के लिए 1.178 करोड़ रुपये की केंद्रीय सब्सिडी दी गई थी। उन्होंने अवगत कराया था कि उपकरण कभी नहीं खरीदे गए थे। पीएम को लिखे अर्ध.सरकारी पत्र में, नाभा ने धन के गबन का आरोप लगाया था और दावा किया था कि एक मंत्री के रूप में उन्हें मशीनरी का कोई विवरण नहीं दिया गया था।

अमृत सरोवर से आशावान है किसानः सीईओ सिंह

हलधर किसान। मप्र के खरगोन जिले में महेश्वर जनपद पंचायत के कुसुम बिया ग्राम पंचायत में बन रहे अमृत सरोवर बनाए जा रहे है। जिला पंचायत सीईओ दिव्यांक सिंह ने निरीक्षण के दौरान यूजर ग्रुप व किसानों से चर्चा की। किसान दसरु, शीतल और उत्तम ने बताया कि तालाब निर्माण से हमारे क्षेत्र में वर्षभर पानी से भरे होने की उम्मीद है। साथ ही आसपास के किसानों के पास पशुओं के लिए कुएँ भी पर्याप्त पेजजल होने की आशा जागी है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम वर्ष में दो फसले ले सकेंगे। साथ ही कई किसान इन सरोवर में मछली पालन के लिए भी उत्साहित दिखाई देने लगे है।

सीईओ श्री सिंह ने सभी किसानों उन्नत किस्मों के मछली बीज व प्रशिक्षण हेतु आजीविका मिशन की टीम को निर्देशित किया है। जनपद पंचायत सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में समीक्षा के दौरान जिन ग्राम पंचायतों का लेबर बजट 15 प्रतिशत से कम हैं उनके सचिव व रोजगार सहायकों का तत्काल वेतन रोकने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा एसबीएम व 15 वित्त के कार्यों की समीक्षा की गई। निरीक्षण दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुरुषोत्तम पाटीदार, जनपद सीईओ मोहन वास्कले, जनपद के सहायक यंत्री एवं परियोजना अधिकारी श्याम रघुवंशी इसके अलावा ग्राम पंचायत के उपयंत्री श्री केरवाल व सचिव रोजगार सहायक भी उपस्थित रहे।

बीज भण्डार™

भारत में तेजी से बढती हुई रिटेल चैन आउटलेट

सभी कंपनियों के उत्कृष्ट क्वालिटी के बीज मिलने का एक मात्र स्थान

मार्केट मूल्य से कम कीमत पर बीज उपलब्ध

बीज भंडार के सीड कार्ड का विमोचन करते हुए माननीय कृषि मंत्री
मध्यप्रदेश शासन श्री कमल जी पटेल एवं खरगोन विधायक श्री रवि जी जोशी

आज ही बीज भंडार में अपनी सदस्यता दर्ज कीजिए और पाइए
आपका स्मार्ट कार्ड – सीड कार्ड।
इतना ही नहीं आपको मिलेंगे सभी कंपनियों
के उच्चतम क्वालिटी के बीज और साथ ही
अर्जित होंगे आपकी हर खरीदी पर अंक।

इसके अलावा कई उत्पादों पर

आकर्षक और विशेष डिस्काउंट

डाउनलोड करें : Google play | अधिक जानकारी के लिए YouTube पर देखें : Beej Bhandar, KisanPlusTv | फॉलो :

ब्रांच-खरगोन/खंडवा/ कुक्षी/बडवाह/राजपुर/अंजड/ धामनोद
इंदौर/ जबलपुर/ मंडलेश्वर/ मनावर/ बरगी/ कसरावद

बीज भंडार की फ्रेंचाईसी लेने के लिए संपर्क करे – 8305103633, 7879428271

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व प्रधान संपादक विवेक जैन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, बलवंत मार्केट, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित व प्रकाशित। Titel Code. MPHIN/2022/37675
, मोबा. नं. 9826225525, 94254 89337, (समस्य प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)। प्रधान संपादक - विवेक जैन, सलाहकार संपादक - पंकज यादव